

Daily Current Affairs

Date : 29 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0 : राजस्थान के 184 गाँवों का चयन
2.	टीबी मुक्त भारत अभियान (100 दिवसीय विशेष अभियान)
3.	उमंग - VII : बालश्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध राजस्थान पुलिस का अभियान
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. एन्टी मलेरिया मंथ (जून, 2026) 2. सक्षम अग्रवाल : राज्यपाल के नए परिसहाय 3. प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान - 2026 4. दिव्यांशी जैन : 33वीं लिनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक 5. भरतपुर के 'अपना घर आश्रम' का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 6. श्री देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव : सवाई माधोपुर 7. स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SPPP) और सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP)
5.	जनसांख्यिकीय बदलाव पर उच्च-स्तरीय समिति
6.	भारत की 'जल बजट' पहल से भूजल स्तर में सुधार
7.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (TEXPROCIL)
8.	हाइड्रोजन ईंधन सेल
9.	अनुच्छेद 142: न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण
10.	पीएम-वाणी (PM-WANI) योजना
11.	पीएम-अजय (PM-AJAY)
12.	सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) योजना
13.	क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD)
14.	लॉन्ग-टैल्ड डस्कहॉकर
15.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2022-23

---1---



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR



राजस्थान परिदृश्य



वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0 : राजस्थान के 184 गाँवों का चयन



चर्चा में क्यों?

- 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0' के अंतर्गत राजस्थान के 5 सीमांत जिलों; जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं फलौदी के 184 रणनीतिक महत्त्व के गाँवों में 10 विषयगत क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा।



मुख्य बिन्दु:

जिले-वार गाँवों की संख्या :

जिला	चयनित गाँवों की संख्या
श्रीगंगानगर	68
बीकानेर	46
बाड़मेर	36
जैसलमेर	30
फलौदी	4
कुल	184

- **वित्तीयन :** कार्यक्रम के अनुसार राज्य के रणनीतिक गाँवों में विकास एवं योजनाओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष ₹3 करोड़ का प्रावधान।

Daily Current Affairs

Date : 29 May, 2026



- राजस्थान में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0' सीमान्त क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पश्चात अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों का समग्र विकास करने संबंधी केन्द्र सरकार की दूसरी बड़ी योजना है।
- इस परियोजना के तहत इन गाँवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, ऑन ग्रिड विद्युतीकरण के क्षेत्र में शत-प्रतिशत संतृप्त किया जाएगा।
- साथ ही, इन गाँवों को आजीविका सृजन, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यटन एवं संस्कृति का विकास, आजीविका एवं कौशल विकास, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठनों का विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0

- 4 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0' को स्वीकृति प्रदान की।
- अवधि : वर्ष 2024-2029

प्रोग्राम का नाम	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम - 2.0
लॉन्च	2023	2025
राज्य	अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (UT), लद्दाख (UT), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा गाँवों में।

--3--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

Daily Current Affairs

Date : 29 May, 2026



वित्त पोषण	शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा।	शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा।
उद्देश्य	सीमावर्ती गाँवों में जीवन स्तर में सुधार और आजीविका के अवसर सृजित करना। स्थानीय आबादी को सीमा बलों के समर्थन के रूप में शामिल करके सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना। सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना और सीमावर्ती समुदायों को देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत करना।	सीमावर्ती गाँवों में जीवन स्तर में सुधार और आजीविका के अवसर सृजित करना। स्थानीय आबादी को सीमा बलों के समर्थन के रूप में शामिल करके सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना। सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना और सीमावर्ती समुदायों को देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत करना।
संबंध मंत्रालय	गृह मंत्रालय।	गृह मंत्रालय।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** : राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषित की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने ₹150 करोड़ का प्रारंभिक बजट स्वीकृत किया है। कार्यक्रम के तहत राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गाँवों का समग्र विकास किया जाना प्रस्तावित है।

-:4:-

टीबी मुक्त भारत अभियान (100 दिवसीय विशेष अभियान)

चर्चा में क्यों?

- विश्व TB दिवस (24 मार्च) के अवसर पर शुरू किए 'टीबी मुक्त भारत अभियान - 100 दिवसीय विशेष अभियान' के तहत राजस्थान में 18.93 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 32,000 से अधिक नए टीबी मरीजों की पहचान की गई।

मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान में यह 100 दिवसीय विशेष अभियान 11,328 हाई रिस्क गाँवों एवं वार्डों में संचालित किया जा रहा है।
- **TB स्क्रीनिंग में राजस्थान का स्थान :** वर्ष 2025 में राजस्थान ने 1 करोड़ 75 लाख से अधिक संभावित टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- **नोट :** वर्ष 2024 में राजस्थान 'टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान' में देश में तीसरे स्थान पर रहा था। अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया।
- **नोट :** वर्ष 2025 में प्रदेश की 6,547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है।
- **क्षयरोग (TB) :** क्षयरोग (टीबी) एक जीवाणुजनित संक्रमण है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, किंतु यह पेट, ग्रंथियों, हड्डियों तथा तंत्रिका तंत्र जैसे शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है।



Daily Current Affairs

Date : 29 May, 2026



फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान :

- **शुरुआत :** 9 सितम्बर, 2022
- **सम्बद्ध मंत्रालय :** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार)
- **लक्ष्य :** वर्ष 2025 तक टीबी का उन्मूलन।
- **वैश्विक लक्ष्य :** वर्ष 2030 है।

'टीबी मुक्त पंचायत' पहल:

- 24 मार्च, 2023 को विश्व ट्यूबरकलोसिस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से।
- यह टीबी के लिए लघु निवारक उपचार और परिवार-केंद्रित देखभाल मॉडल की आधिकारिक अखिल भारतीय पहल है।

वैश्विक प्रयास:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा "Find. Treat. All. #EndTB" संयुक्त पहल ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ शुरू की गई है।
- प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस (World Tuberculosis Day) मनाया जाता है।
- **वर्ष 2026 के विश्व TB दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम :** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में।
- **वर्ष 2026 की विषयवस्तु (Theme) :** हाँ! हम TB को खत्म कर सकते हैं! देशों के नेतृत्व में। लोगों की शक्ति से। (Yes! We can End TB! Led by countries. Powered by people)

--:6::--

उमंग - VII : बालश्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध राजस्थान पुलिस का अभियान

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में बालश्रम, बाल बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार (बाल तस्करी) के खिलाफ 1 से 30 जून, 2026 तक राज्यव्यापी विशेष अभियान 'उमंग - VII' का संचालन किया जा रहा है।



पुलिस मुख्यालय, राजस्थान

सेवा ★ सुरक्षा ★ समर्पण

बालश्रम, बाल बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार (बाल तस्करी) के उन्मूलन हेतु

विशेष अभियान

“उमंग - VII”

आइए मिलकर बनायें
बालश्रम मुक्त
एवं सुरक्षित राजस्थान

“हर बच्चा सुरक्षित - हर बच्चा शिक्षित”

01 जून 2026 से 30 जून 2026 तक



मुख्य बिन्दु:

- अभियान का संचालन :** राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसियों के सहयोग से।
- अभियान का उद्देश्य :** बालश्रम एवं बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना।
- टैगलाइन :** 'हर बच्चा सुरक्षित - हर बच्चा शिक्षित'।
- जिला स्तर पर नोडल अधिकारी :** अभियान के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

- अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति, शेल्टर होम, चिल्ड्रन होम तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ संयुक्त रणनीति तैयार की जाएगी।
- यदि किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा मानव तस्करी या बाल श्रम से जुड़े मामले सामने आते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143, 144, 145, 146, 98 एवं 99 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- **भारतीय संविधान में प्रावधान :** बालश्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और मानव दुर्व्यापार (बाल तस्करी) को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए भाग - III (मौलिक अधिकार) और भाग - IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) के तहत विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।
- **अनुच्छेद - 23 (1) :** मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद - 24 :** कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध - चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
- **अनुच्छेद - 39 (e) :** राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व - पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।
- **अनुच्छेद 39 (f) :** बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। (इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।)

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	एन्टी मलेरिया मंथ (जून, 2026) ■ मलेरिया उन्मूलन की दिशा में जन-जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, मजबूत सर्विलांस एवं समय पर जाँच एवं उपचार सुनिश्चित करने के लिए जून, 2026 को राज्यव्यापी 'एन्टी मलेरिया मंथ' के रूप में मनाया जाएगा। ■ संचालन : केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र द्वारा। ■ केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ■ एन्टी मलेरिया मंथ के तहत 16 से 30 जून, 2026 तक हैचरीज क्रियाशील पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें पानी के गढ़ों में गम्बूशिया मछलियाँ छोड़ी जाएँगी।
2.	सक्षम अग्रवाल : राज्यपाल के नए परिसहाय ■ हाल ही में, स्ववाङ्मन लीडर सक्षम अग्रवाल ने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे के नए परिसहाय (Aide-de-Camp - ADC) के रूप में पदभार ग्रहण किया। ■ परिसहाय (Aide-de-Camp) राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे शीर्ष संवैधानिक प्रमुखों के निजी सहायक और सुरक्षा व प्रोटोकॉल के समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
3.	प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान - 2026 ■ पुरस्कृत : जोधपुर की डॉ. नीना छिब्बर। ■ प्रदानकर्ता : मेदनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था।

4.	दिव्यांशी जैन : 33वीं लिनिंग एशियन जूनियर स्ववैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक ■ चीन के पान्झीहुआ में आयोजित 33वीं लिनिंग एशियन जूनियर स्ववैश चैंपियनशिप - 2026 में जयपुर की दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर-13 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। ■ इस चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल 8 पदक (1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य) जीते।
5.	भरतपुर के 'अपना घर आश्रम' का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ■ भरतपुर में स्थित 'अपना घर आश्रम' ने 3,295 निराश्रित और असहाय महिलाओं को सम्मानजनक आश्रय और चिकित्सा सेवा प्रदान कर दुनिया के सबसे बड़े महिला निराश्रित आश्रय गृह के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया।
6.	श्री देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव : सवाई माधोपुर ■ 28 से 30 मई, 2026 तक सवाई माधोपुर के कुशालीदर्द में 'श्री देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव' का आयोजन किया गया।
7.	स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SPPP) और सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) ■ राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए सभी राजकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और स्वायत्त निकायों हेतु स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SPPP) और नए एकीकृत सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) के उपयोग को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। ■ यह कदम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को लागू करने और मैन्युअल खरीद में होने वाली गड़बड़ियों को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ■ स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SPPP) : यह राजस्थान सरकार का मुख्य सूचनात्मक पोर्टल है, जहाँ सभी सरकारी विभागों की निविदाओं (Tenders) की जानकारी सार्वजनिक की जाती है। ■ सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) : यह राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी, 2026 में लॉन्च किया गया एक उन्नत एकीकृत डिजिटल सिस्टम है।



भूगोल एवं भू-विज्ञान



जनसांख्यिकीय बदलाव पर उच्च-स्तरीय समिति

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलाव पर उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करेगी और इनसे निपटने के उपाय सुझाएगी।



मुख्य बिन्दु:

- इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे। इसके सदस्यों में शामिल हैं; जनगणना आयुक्त और तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ।

समिति को सौंपे गए कार्य

- सीमा-पार कारकों आदि के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों के कारणों और चुनौतियों पर विचार एवं अध्ययन करना
- धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या की संरचनात्मक बदलावों का विश्लेषण करना
- सीमा प्रबंधन, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए संस्थागत एवं कार्यात्मक तंत्र की सिफारिश करना।

भारत में अवैध प्रवासन के कारण

- **उत्पीड़न से बचकर आने वाले लोगों के लिए गंतव्य:** उदाहरण के लिए म्यांमार से आए रोहिंग्या।
- **आर्थिक कारण:** इसमें पड़ोसी देशों में गरीबी, रोजगार के अवसरों की कमी, आय में कमी आदि।
- **पर्यावरणीय कारण:** उदाहरण- बांग्लादेश में बार-बार आने वाली बाढ़, चक्रवात और नदी के कटाव के कारण लोगों का विस्थापन।

-:11:-

भारत की 'जल बजट' पहल से भूजल स्तर में सुधार

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- अटल भूजल योजना के तहत 2023-24 और 2024-25 में किए गए आकलन के अनुसार, 229 में से 180 ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार देखा गया है।



मुख्य बिन्दु:

जल बजट (Water Budgeting)

- **परिभाषा:** यह एक व्यवस्थित आकलन है, जिसमें किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र (जैसे गाँव, जलग्रहण क्षेत्र, ब्लॉक) में जल की उपलब्धता और माँग का आकलन किया जाता है, ताकि जल का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- **गणना:** इसमें जल की प्राप्ति (वर्षा जल, सतही जल प्रवाह, भूजल पुनर्भरण) और जल की खपत (वाष्पोत्सर्जन, बहाव, भूजल दोहन) का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

जल बजट में सहायक सरकारी पहलें:

- **अटल भूजल योजना(2019):** यह ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट बनाना अनिवार्य करती है तथा गोकट्टे, बावड़ी, जोहड़ और टांका जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों का कायाकल्प करती है।
- **राष्ट्रीय जल मिशन:** यह मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के तहत जल बजट को बढ़ावा देता है। इसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **वरुणी ऐप:** यह ऐप नीति आयोग के सहयोग से भारत-जर्मन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह बारिश और भूमि उपयोग से संबंधित डेटा का उपयोग करता है और स्वचालित रूप से ब्लॉक-स्तरीय जल बजट तैयार करता है।

राज्य-स्तरीय पहलें:

- **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (राजस्थान):** वर्ष 2016 में प्रारंभ यह अभियान चार जल-स्रोतों की अवधारणा पर आधारित है। इससे भूजल स्तर में लगभग 4% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **जलयुक्त शिवार अभियान (महाराष्ट्र):** वर्ष 2014 में जियोटैगिंग और ऐप-आधारित निगरानी के साथ शुरू इस अभियान ने 11,000 से अधिक गाँवों को सूखा-मुक्त बनाने में मदद की।



आर्थिक घटनाक्रम



सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (TEXPROCIL)

(स्रोत: DD NEWS)



TEXPROCIL

THE COTTON TEXTILES EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By Government of India)



मुख्य बिन्दु:

- हाल ही में 'TEXPROCIL निर्यात पुरस्कार 2023-24' समारोह के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वस्त्र क्षेत्रक के लिए निम्नलिखित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दोहराया:
 - निर्यात लक्ष्य: 100 बिलियन डॉलर
 - उत्पादन लक्ष्य: 250 बिलियन डॉलर (वर्ष 2030 तक)

TEXPROCIL

- **स्थापना:** वर्ष 1954
- **मुख्यालय:** मुंबई
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय।
- **स्वरूप:** यह सरकार द्वारा प्रायोजित, एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संस्था है।
- **मुख्य कार्य:** यह वैश्विक स्तर पर भारत के सूती वस्त्रों का प्रतिनिधित्व करती है और विश्व भर में भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करती है।

-:14:-

हाइड्रोजन ईंधन सेल

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- भारतीय रेलवे ने जींद-सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रेन की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की।



मुख्य बिन्दु:

हाइड्रोजन ईंधन सेल

- **परिभाषा:** यह एक विद्युत-रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- **कार्यप्रणाली:** पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों के विपरीत, फ्यूल सेल बिना ईंधन जलाए बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता। इनके केवल उप-उत्पाद जल और ऊष्मा होते हैं।
- **ईंधन सेल के प्रमुख प्रकार:** प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, अल्कलाइन फ्यूल सेल, आदि।

--:15::--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

अनुच्छेद 142: न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण

(स्रोत: THE HINDU)



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए 'राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार 'जीवन का अधिकार' का एक अभिन्न अंग घोषित किया।



मुख्य बिन्दु:

- न्यायालय ने व्यापक निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुरक्षित, अच्छी तरह से रखरखाव वाली और चलने योग्य सड़कें उपलब्ध कराना राज्य का बाध्यकारी संवैधानिक कर्तव्य है, न कि केवल एक नीतिगत उद्देश्य।

अनुच्छेद 142 क्या है?

- पूर्ण न्याय:** इस अनुच्छेद के तहत, उच्चतम न्यायालय (SC) को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री जारी करने का अधिकार है, जहाँ वर्तमान कानून कोई विशेष समाधान प्रदान करने में असफल हों।
- उच्च न्यायालयों को उपलब्ध नहीं है:** अनुच्छेद 142 के तहत उपर्युक्त शक्तियाँ संवैधानिक रूप से केवल उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई हैं।
- महत्त्व:** यह अनुच्छेद विधायी प्रावधानों की अनुपस्थिति की समस्या को दूर करता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहाँ स्पष्ट अन्याय दिखाई दे लेकिन उसे दूर करने के लिए कोई स्पष्ट कानून न हो, तो अनुच्छेद 142 न्यायालय को हस्तक्षेप कर तत्काल समाधान प्रदान करने की शक्ति देता है।

- **उदाहरण के लिए:** कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने के लिए 1997 में विशाखा दिशा-निर्देश, क्योंकि उस समय इस विषय पर कोई सांविधिक कानून मौजूद नहीं था।
- **आलोचना:** हालांकि, यह अनुच्छेद कानून के अभाव को दूर करने के लिए एक 'संवैधानिक सुरक्षा वाल्व' है, लेकिन इससे कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- न्यायिक अतिक्रमण वह स्थिति है, जब न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार कर कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है।
न्यायिक अतिक्रमण से संबद्ध चिंताएँ:
- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:** उदाहरण- BCCI में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा लोढ़ा पैनल का गठन।
- **जवाबदेही में कमी आना:** जब नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कमजोर हो जाता है तो जवाबदेही में कमी आती है। उदाहरण- उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग- 2015 को निरस्त कर दिया।
- **सभी विषयों पर विशेषज्ञता का अभाव:** उदाहरण-तमिलनाडु बनाम के. बालू वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रातों-रात लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गईं।
- **कार्यपालिका की सीमाओं की अनदेखी:** न्यायालय कई बार संसाधनों या अवसंरचना की सीमाओं पर विचार किए बिना निर्देश जारी कर देते हैं।
- **उदाहरण-** एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2018) वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए BS-IV वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

📦 योजनाएँ एवं नीतियाँ 📦

पीएम-वाणी (PM-WANI) योजना

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना को यूजर-फ्रेंडली उन्नयन प्राप्त हुआ है।



मुख्य बिन्दु:

- इस योजना के तहत पहुँच को बेहतर बनाने के लिए QR-आधारित लॉगिन, कम अवधि वाले प्लान और मानकीकृत हॉटस्पॉट नाम शुरू किए गए हैं।

पीएम-वाणी

- **मंत्रालय:** संचार मंत्रालय
- **प्रारंभ:** वर्ष 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा।
- **उद्देश्य:** देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक सुदृढ़ डिजिटल संचार अवसंरचना के निर्माण हेतु सार्वजनिक वाई-फाई (WiFi) हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाना।

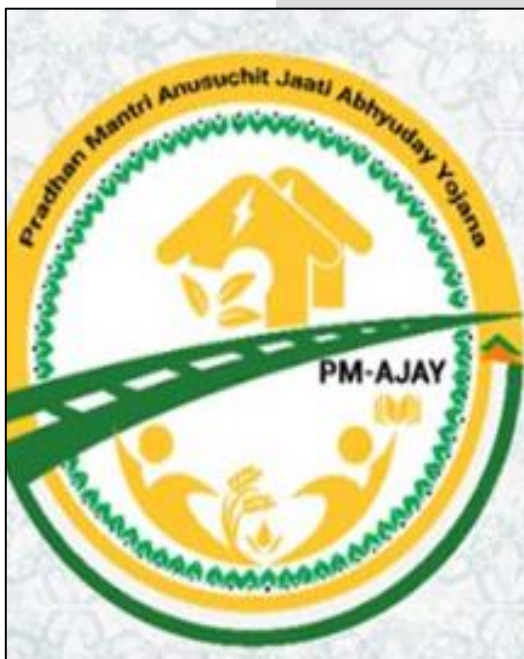
पीएम-अजय (PM-AJAY)

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 'पीएम-अजय' पोर्टल और 'अजय' (AJAY) मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।



Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY)



मुख्य बिन्दु:

- पीएम-अजय पोर्टल के अंतर्गत आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास घटकों के लिए रियल-टाइम निगरानी, पारदर्शी प्रशासन और निर्धारित लक्ष्यों से संबद्ध वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)

- शुभारंभ: वर्ष 2021-22
- इसे निम्नलिखित 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विलय करके प्रारंभ किया गया है-

Daily Current Affairs



Date : 29 May, 2026



- o प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY),
- o अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP)
- o बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)।
- **उद्देश्य:** अनुसूचित जातियों (SCs) का सामाजिक-आर्थिक उत्थान।
- **मुख्य क्षेत्र:** गरीबी न्यूनीकरण, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि, और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना में सुधार।
- **वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त-पोषित।
- **क्रियान्वयन:** केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- **विस्तार:** 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES



सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) योजना

(स्रोत: DD NEWS)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक बनाने के लिए सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) योजना को मंजूरी दी।



मुख्य बिन्दु:

- सार्थक-पीडीएस से आशय है; “राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता - सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय योजना” (Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS: SARTHAK-PDS)
- यह योजना निम्नलिखित दो पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है:
 - o NFSA के तहत खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय आवागमन और FPS डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और

o सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना (SMART PDS)।

सार्थक-PDS के मुख्य बिंदु

- **योजना-अवधि:** 31 मार्च, 2031 तक (16वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक)।
- **बजट:** अगले पाँच वर्षों के लिए ₹25,530 करोड़ का आवंटन।
- **लाभार्थी:** इसका लाभ 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा।

मुख्य विशेषताएँ:

- वितरण नेटवर्क की वास्तविक समय में निगरानी के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस, AI आधारित विश्लेषण डैशबोर्ड, स्वचालित शिकायत निवारण प्रणाली आदि का उपयोग किया जाएगा।

उद्देश्य:

- राज्य के भीतर अनाज के परिवहन, भंडारण/प्रबंधन और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- अंतिम छोर तक बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और रिसाव (लीकेज) कम करने के लिए एकीकृत, नागरिक-केंद्रित और आपस में जुड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) विकसित करना।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD)

(स्रोत: INDIAN EXPRESS)



चर्चा में क्यों?

- क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD) के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में क्वाड देशों; भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।



मुख्य बिन्दु:

घोषित की गई प्रमुख पहलें

- **क्वाड क्रिटिकल-मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क:** यह 20 अरब डॉलर की पहल है। इसका उद्देश्य खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में निवेश का समन्वय करना है। इससे वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

--:23:--

- **हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग (IPMSC):** प्रारंभ में इसका मुख्य ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र पर होगा। यह पहल क्वाड देशों की संयुक्त निगरानी क्षमताओं का उपयोग करके वास्तविक समय में सूचना साझा करने तथा समुद्री गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायता करेगी।
- **क्वाड ऊर्जा सुरक्षा पहल:** इस पहल के माध्यम से क्वाड के साझेदार देश खुले और स्थिर ऊर्जा बाजार तथा विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की पहचान करेंगे।
- **हिंद-प्रशांत कनेक्टिविटी:** वर्ष 2026 तक प्रशांत द्वीपीय मंच के देशों को समुद्र में जल के नीचे बिछाई गई केबलों से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। साथ ही, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत फिजी में बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
- **UNCLOS के प्रति प्रतिबद्धता:** क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS) का अनुपालन करने पर जोर दिया ताकि लाल सागर, होमुर्ज जलसंधि और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहे।
- **तटरक्षक बल के नेतृत्व में 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन':** समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत इस मिशन के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा।
- **6G संचार:** क्वाड देश मिलकर अगली पीढ़ी के संचार मानकों, विशेष रूप से 6G तकनीक के विकास पर कार्य करेंगे।

क्वाड (QUAD)

- **सदस्य:** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
- **इतिहास:** इसकी शुरुआत, 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद मानवीय सहायता पहुँचाने में समन्वय के लिए की गई थी।

-:24:-

Daily Current Affairs

 Date : 29 May, 2026



- **2007:** तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक संवाद के रूप में प्रस्तावित किया, लेकिन बाद में यह निष्क्रिय हो गया।
- **2017:** नियम-आधारित व्यवस्था और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंताओं के कारण इसे फिर से सक्रिय किया गया।
- **प्रभाव:** क्वाड समूह विश्व की 24% आबादी, 35% GDP और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत के लिए क्वाड का महत्व
- **चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना:** हिंद महासागर क्षेत्र में किसी एक देश के वर्चस्व को संतुलित करने के लिए क्वाड महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से वार्षिक 'मालाबार' नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है।
- **आर्थिक और जलवायु क्षेत्रों में सहयोग:** आर्थिक सहयोग (जैसे - क्वाड निवेश नेटवर्क, 2024); जलवायु क्षेत्र में सहयोग (जैसे - क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज) आदि।

-:25:-

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

लॉन्ग-टेल्ड डस्कहॉकर

(स्रोत: THE HINDU)



चर्चा में क्यों?

- नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में एक ड्रैगनफ्लाई, लॉन्ग-टेल्ड डस्कहॉकर की उपस्थिति दर्ज की गई है।



मुख्य बिन्दु:

- ड्रैगनफ्लाई 'ओडोनाटा' क्रम से संबंधित हैं, ये विश्व के सबसे तेज उड़ने वाले कीटों में गिने जाते हैं और इनका लगभग 360-डिग्री का दृष्टि क्षेत्र होता है।
- ये ताजे जल के जलीय पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं।





नामदफा राष्ट्रीय उद्यान

- **अवस्थिति:** यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत, म्यांमार और चीन के ट्राइजंक्शन बिंदु पर स्थित है।
- इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी, नोआ-दिहिंग नदी का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है।
- इस उद्यान का सर्वोच्च बिंदु दाफा बूम है।
- इसकी सीमाएँ कामलांग वन्यजीव अभयारण्य, पटकाई पर्वतमाला और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं।



⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2022-23

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान 2022-23 जारी। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय द्वारा तैयार किया गया है।

National Health Accounts (NHA) estimates for India 2022-23



मुख्य बिन्दु:

NHA 2022-23 रिपोर्ट के बिंदु

- देश की जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2013-14 की 1.15% से बढ़कर 2022-23 में 1.43% हो गई।
- सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय 2013-14 के ₹0.5 लाख करोड़ से दोगुने से अधिक होकर 2022-23 में ₹1.4 लाख करोड़ हो गया।

--:28:--

Daily Current Affairs

Date : 29 May, 2026



- लोगों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला (आउट ऑफ पॉकेट) स्वास्थ्य व्यय 2013-14 और 2022-23 के बीच 64.2% से घटकर 43.4% पर आ गया।
- स्वास्थ्य देखभाल पर सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE) 2013-14 और 2022-23 के बीच 6% से बढ़कर 9.9% हो गया।

स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकारी पहलें:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:** इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी, विशेषकर कमजोर वर्गों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है।
- **आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना:** यह योजना माध्यमिक और तृतीयक स्तर के उपचारों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर पात्र प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य-बीमा कवर प्रदान करती है।
- **प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना:** इसका उद्देश्य ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराना है।